

रायपुर में सुशासन सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रायपुर में **सुशासन** पर दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के तहत शुरू किये गए शासन सुधारों में **"ईज़ ऑफ लविंग"** और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है ।

प्रमुख बदि

- कार्यक्रम विवरण:
 - प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग (DARPG) और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया ।
 - सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारों पर चर्चा करने के लिये नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ।
- विकेंद्रीकृत शासन पर चर्चा:
 - शासन संबंधी चर्चाओं को सतता के केंद्रीय कक्षों से आगे ले जाने के महत्त्व पर बल दिया गया ।
 - राज्यों में आयोजित सम्मेलनों से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान सुनिश्चित होते हैं तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला है ।
 - इसी प्रकार के कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में भी आयोजित किये गए, जो राष्ट्रव्यापी पहुँच को दर्शाते हैं ।
- ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार:
 - नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के लिये 2,000 से अधिक अप्रचलित नियमों को हटा दिया गया है ।
 - सत्यापित दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिससे नागरिकों में विश्वास मज़बूत हुआ ।
 - पेंशनभोगियों के लिये चेहरा पहचानने वाली तकनीक शुरू की गई, जिससे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो गई ।
 - समय पर भुगतान के लिये पेंशन और परिवार पात्रता प्रणालियों का डिजिटलीकरण बढ़ाया गया ।
 - गुरुप B और C के पदों के लिये साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पक्षपात और भ्रष्टाचार कम हो गया ।
- सुधारों का प्रभाव:
 - शासन सुधारों का उद्देश्य वलिंब को कम करना, भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिकों के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ।
 - कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया, जिससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण आबादी को लाभ मिला ।

सुशासन



विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन वह माध्यम है जिसके द्वारा विकास के लिये किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

संदर्भ

- भगवद् गीता
- **कौटिल्य का अर्थशास्त्र**: राजा की भूमिका में प्रजा का कल्याण सर्वोपरि माना जाता है
- महात्मा गांधी ने "सु-राज" (सुशासन) पर ज़ोर दिया है
- **सतत विकास लक्ष्य 16**: शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकार और सुरक्षा में सुधार

मुख्य विशेषताएँ (मानवाधिकार परिषद् के अनुसार)

- ⌚ पारदर्शिता
- ⌚ ज़िम्मेदारी
- ⌚ जवाबदेहिता (Responsibility)
- ⌚ भाग लेना (Participation)
- ⌚ जवाबदेही (Responsiveness) [लोगों की आवश्यकताओं के प्रति]

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गए 8 सिद्धांत



भारत में सुशासन नामक पहल

राष्ट्रीय सुशासन दिवस: 25 दिसंबर (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से)

■ पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

- ⌚ सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19 (1)) और RTI अधिनियम, 2005
- ⌚ ई-गवर्नेंस (न्यूनतम सरकार - अधिकतम गवर्नेंस); डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- ⌚ केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

■ विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन

- ⌚ नीति आयोग (सहकारी संघवाद)
- ⌚ 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

■ नागरिक भागीदारी और सशक्तीकरण

- ⌚ मेक इन इंडिया पहल, MyGov प्लेटफॉर्म, RTE अधिनियम, 2009

■ वैधानिक सुधार

- ⌚ मॉडल पुलिस अधिनियम (2015), e-FIR, e-कोर्ट प्रोजेक्ट, SUPACE पोर्टल

■ सुशासन सूचकांक (इसे DARPG द्वारा तैयार किया जाता है)

संबंधित चुनौतियाँ

- ⌚ **भ्रष्टाचार**: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2023 में भारत 93/180वें स्थान पर है
- ⌚ **असमानता और सामाजिक बहिष्कार**: भारत में धन की असमानता 60 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है (वर्ष 2024 में) (शीर्ष 1% लोगों के पास 40.1% संपत्ति है)
- ⌚ **अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना**: विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, (मात्र उच्चतम न्यायालय में ~80,000)

सुझाव

- ⌚ नीतिगत निर्णयों में नागरिकों को शामिल करने के लिये एक सुरक्षित डेटा प्लेटफॉर्म निर्माण की आवश्यकता है
- ⌚ AI-संचालित शिकायत निवारण
- ⌚ **सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model)**: सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिये

